



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 505]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 1980/कार्तिक 13, 1902

No. 505]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4, 1980/KARTIKA 13, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय

(अर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1980

का० प्रा० 875 (अ):—केन्द्रीय सरकार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों  
का अर्जन और अन्तर्गण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा  
9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिजर्व बैंक के परामर्श करने  
के पश्चात् निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

अध्याय 1

परिचालक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम  
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रवर्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1980 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगी जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र  
में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं—इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित  
न हो,—

(क) “अधिनियम से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तर्गण)  
अधिनियम, 1980 (1980 का 40) अभिप्रेत है,

(ख) “उपाबन्ध” से इस अधिनियम से संलग्न उपाबन्ध अभिप्रेत है,

(ग) “वोर्ड” से खंड 3 के अधीन गठित निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है,

(घ) “अध्यक्ष” से, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के संबंध में, उस बैंक के  
बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) “निदेशक” से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का तत्काल निदेशक  
अभिप्रेत है;

(च) “राष्ट्रीयकृत बैंक” से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा  
(1) के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक अभिप्रेत है;

(छ) “प्रतिनिधि संघ” से अधिनियम संघ अधिनियम, 1926 (1926  
का 16) के अधीन राजनीकृत संघ या ऐसे संघों का परिसंघ  
अभिप्रेत है, यदि, यथास्थिति, ऐसे संघ या परिसंघ के बारे में,  
सम्यक् सत्यापन के पश्चात् यह प्रमाणित किया जाता है कि  
राष्ट्रीयकृत बैंक में नियोजित अधिकांश कर्मकार इसके ऐसे सदस्य  
हैं जिन्होंने अपने देय, संघ को या परिसंघ गठित करने वाले  
संघों में से किसी को नियमित रूप से संचित कर दिए हैं;

परन्तु, यथास्थिति, ऐसे किसी संघ या परिसंघ को इस स्कीम  
के प्रयोजनों के लिए तब तक प्रतिनिधि संघ नहीं समझा जाएगा  
जब तक कि, यथास्थिति, ऐसे संघ या परिसंघ गठित करने वाले  
संघों की सत्यापित सदस्यता राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा नियोजित  
कर्मकारों को कुल संख्या का पन्द्रह प्रतिशत या अधिक न  
हों;

(ज) “अनुसूची” से इस स्कीम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(झ) “सत्यापन” से, इसके आधिकारिक रूप में और सजातीय पदों  
सहित मुख्य धर्म आपुस्त (केन्द्रीय) द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट  
प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन अभिप्रेत है;

- (ब) "कर्मकार" का वही अर्थ है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (घ) में है ;
- (ट) जो शब्द और पद इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं उनके वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

### अध्याय 2

#### निदेशक बोर्ड

3. बोर्ड का गठन—केन्द्रीय सरकार, इस स्कीम के प्रारम्भ के पश्चात् षष्ठाशीष्ठ, राजपत्र में अधिवृत्तना द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक का निदेशक बोर्ड गठित करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

- (क) दो से अधिक पूर्णकालिक निदेशक, जिनमें से एक प्रबन्ध निदेशक होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किए जाएंगे ;
- (ख) (1) राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारियों में से, जो कर्मकार हैं, एक निदेशक जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे तीन कर्मचारियों के पैनल में से नियुक्त किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर प्रतिनिधि संघ द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह तारीख केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सूचना की तारीख से, जिसमें प्रतिनिधि संघ से नामों का पैनल प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है, छः सप्ताह से अधिक की नहीं होगी।

परन्तु जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि प्रतिनिधि संघ के रूप में किसी संघ या परिषद स्थापन के और प्रमाणन में संभावित विसम्ब के कारण राष्ट्रीयकृत बैंक के हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहाँ यह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी कर्मचारी को जो कर्मकार है, उस बैंक का निदेशक नियुक्त कर सकती है।

- (2) (अ) जहाँ राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई प्रतिनिधि संघ नहीं है, या
- (आ) जहाँ ऐसा प्रतिनिधि संघ विद्यमान होते हुए भी विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर नामों का पैनल प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत करने में असफल रहता है, या
- (इ) जहाँ प्रतिनिधि संघ द्वारा प्रस्तुत किए गए पैनल में विनिर्दिष्ट सभी व्यक्ति चाहे इस उपखंड की सब (3) के अधीन या खंड 10 के अधीन निरहित हैं।

वहाँ केन्द्रीय सरकार अपने विवेकानुसार, राष्ट्रीयकृत बैंक के ऐसे कर्मकार को जो वह ठीक समझे, ऐसे बैंक का निदेशक नियुक्त कर सकती है ;

- (3) राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई कर्मकार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए निरहित होगा, यदि—

(अ) वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में या ऐसे विद्यमान बैंक में जिनका कि वह राष्ट्रीयकृत बैंक तत्स्थानी नया बैंक है, या भागतः एक बैंक में और भागतः दूसरे बैंक में, लगातार पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए सेवा नहीं कर रहा है/करता रहा है ; और

(आ) वह ऐसी आयु का है कि इसकी संभावना नहीं है कि वह निदेशक के रूप में अपनी पदावधि के दौरान ही अपनी अधिराज्यता की आयु प्राप्त करेगा ;

(ग) एक निदेशक जो राष्ट्रीयकृत बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से जो कर्मकार नहीं हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किया जाएगा,

(घ) एक निदेशक जो केन्द्रीय सरकार की राय में विशेषकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने में समर्थ है, बैंक के विशेषकर्ताओं में से, केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किया जाएगा ;

(ङ) तीन निदेशक जो केन्द्रीय सरकार की राय में कृषकों, कर्मकारों और शिल्पियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में समर्थ हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किए जाएंगे ;

(च) पांच से अधिक निदेशक जो ऐसे किसी एक या अधिक विषयों की बाबत जिनकी राष्ट्रीयकृत बैंक के कार्यकरण के लिए उपयोगी होने की संभावना है, विशेष ज्ञान या व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से, केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किए जाएंगे ;

(छ) एक निदेशक जो रिजर्व बैंक का पदाधिकारी है, केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा ;

स्पष्टीकरण :—इस उपखंड के प्रयोजन के लिए रिजर्व बैंक के एक प्राधिकारी में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 51 कक के अन्तर्गत उस बैंक द्वारा उसमें उल्लिखित किसी भी संस्था में प्रतिनियुक्त रिजर्व बैंक का अधिकारी शामिल है।

(ज) एक निदेशक जो केन्द्रीय सरकार का पदाधिकारी है, उस सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

4. बोर्ड का गठन हो जाने पर अभिरक्षकों का पद पर न रह जाना—बोर्ड का गठन हो जाने पर प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे गठन से पूर्व किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अभिरक्षक के रूप में पदधारण कर रहा है, ऐसे पद पर नहीं रहेगा।

5. अध्यक्ष—(1) केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् निदेशकों में से एक बोर्ड को अध्यक्ष नियुक्त करेगी।

(2) अध्यक्ष बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

6. प्रबन्ध निदेशक—(1) प्रबन्ध निदेशक राष्ट्रीयकृत बैंक का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो उसे बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं :

परन्तु जब तक ऐसा प्रत्यायोजन नहीं किया जाता है तब तक प्रबन्ध निदेशक ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी सभी कार्य, कृत्य और बाने करेगा जिन्हें अभिरक्षक, उस तारीख से ठीक पूर्व जिस तारीख को बोर्ड गठित हुआ था, करने या प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत था।

7. एक ही व्यक्ति अध्यक्ष पद प्रबन्ध निदेशक दोनों के रूप में पद धारण कर सकता है :—केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् एक ही व्यक्ति को एक ही समय में अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक दोनों पदों को धारण करने के लिए नियुक्त कर सकती है।

8. पूर्णकालिक निदेशक जिसने अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक है, की पदावधि और पारिश्रमिक :—(1) पूर्णकालिक निदेशक, जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक है, अपना सम्पूर्ण समय राष्ट्रीयकृत बैंक के कार्यालयों में लगाएगा और पांच वर्ष से अधिक ऐसी अवधि तक, जो केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् विनिर्दिष्ट करे, पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(2) उपखंड (1) में किसी बात के होने हुए भी, केन्द्रीय सरकार को किसी पूर्णकालिक निदेशक जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक है, की पदावधि, उसे कम से कम तीन मास की लिखित सूचना या सूचना के बदले में तीन मास के बेलन और भत्ते देकर, उस उपखंड के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार होगा और पूर्णकालिक निदेशक, जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक है, को भी केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में कम से कम तीन मास की सूचना देकर, उस उपखंड के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय अपना पद त्यागने का अधिकार होगा।

(3) पूर्णकालिक निदेशक, जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक है, राष्ट्रीयकृत बैंक से ऐसे वेतन, भत्ते, फीस और परिलब्धियां प्राप्त करेगा और ऐसे निबन्धनों और शर्तों द्वारा शासित होगा जो केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् अवधारित करे

(4) यदि पूर्णकालिक निदेशक, जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक है, अंगशैथिल्य के कारण या अन्यथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है या ऐसी परिस्थितियों में जिनके अन्तर्गत उसके पद का रिक्त होना नहीं है, छुट्टी लेकर अनुपस्थित है या अन्यथा अनुपस्थित है तो केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् किसी अन्य व्यक्ति को उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसके स्थान पर कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकती है।

(5) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समझाया जाता है कि ऐसा करना राष्ट्रीयकृत बैंक के हित में समीचीन है तो वह पूर्णकालिक निदेशक को जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक है, पद से हटा सकती है :

परन्तु इस प्रकार पद से हटाने की कार्यवाही—

(क) बोर्ड से परामर्श करने के, और

(ख) पूर्णकालिक निदेशक, जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक है, को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध हेतुक दायित्व करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ही की जायगी, अन्यथा नहीं।

9 अन्य निदेशकों की पदावधि:—(1) खंड 3 के उपखंड (ख), (ग), (घ), (ङ) या (च) के अधीन नियुक्त निदेशक तीन वर्ष से अधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् उसके द्वारा उस खंड के उपखंड (ख), (ग), (घ), (ङ) या (च) के अधीन नियुक्त किसी निदेशक को पद से हटा सकेगी और रिक्ति को भरने के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी :

परन्तु यह और कि निदेशक को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध हेतुक दायित्व करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ही पद से हटाया जाएगा।

(2) खंड 3 के उपखंड (छ) या उपखंड (ज) के अधीन नियुक्त किया गया निदेशक केन्द्रीय सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(3) कोई निदेशक जिसकी पदावधि समाप्त हो गई है, ऐसी समाप्ति के होने हुए भी, तब तक निदेशक के रूप में पद धारण करता रहेगा तब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता।

10 निदेशकों की निरुहताएं:—कोई व्यक्ति निदेशक नियुक्त किए जाने और निदेशक होने के लिए निरुहता होगा,—

(क) यदि उसे किसी समय दिवालिया न्यायानिर्णय किया गया है या उसने संशय निरक्षित कर दिया है या उसने अपने लेनदारों से समझौता कर लिया है, या

(ख) यदि उसे विरुद्ध चलाया गया है और नक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया है, या

(ग) यदि उसे वाणिज्य न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दोष-मिद्ध किया गया है जिसमें नैतिक प्रक्षमता अन्तर्बलित है।

11 निदेशकों की रिक्ति: (1) यदि कोई निदेशक खंड 10 में विनिर्दिष्ट किसी निरुहता से ग्रस्त हो जाता है, या बोर्ड की इजाजत के बिना उसके तीन से अधिक कर्मचारी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उस हैसियत में अपना पद रिक्त कर दिया है और तब उसका पद रिक्त हो जाएगा।

(2) अध्यक्ष या कोई पूर्णकालिक निदेशक जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक है, या खंड 3 के उपखंड (छ) या उपखंड (ज) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निदेशक केन्द्रीय सरकार को उसकी लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा और ऐसे त्यागपत्र के उस सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है तथा कोई अन्य निदेशक केन्द्रीय सरकार को उसकी लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा त्यागपत्र की समूचना की प्राप्ति पर प्रभावी होगा।

(3) पूर्वेगामी उपखंडों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना, खंड 3 के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट किसी निदेशक का पद, जैसे ही वह निदेशक उस राष्ट्रीयकृत बैंक का जिसका वह है, कर्मकार या कर्मकार से भिन्न कर्मचारा न रहने पर; रिक्त हो जाएगा तथा खंड 3 के उपखंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट निदेशक का पद, ऐसे निदेशक के उस राष्ट्रीयकृत बैंक का जिसका वह निदेशक है निक्षेप-कर्ता न रहने पर रिक्त हो जाएगा।

(4) जहां किसी निदेशक की पदावधि की समाप्ति से पूर्व कोई रिक्ति हो जाती है वहां वह खंड 3 के अनुसार भरी जाएगी।

(5) खंड 3 के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) या उपखंड (घ) या उपखंड (ङ) या उपखंड (च) के अधीन किसी निदेशक के पद की किसी रिक्ति में उपखंड (4) के अधीन नामनिर्दिष्ट निदेशक तीन वर्ष से अधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु खंड 3 के उपखंड (ख) की मद (i) के परन्तुक के अधीन या मद (ii) के अधीन नियुक्त कोई निदेशक एक समय पर छ. मास से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा।

(6) किसी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त कोई अन्य निदेशक इस स्कीम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, या केन्द्रीय सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

12 बोर्ड के अधिवेशन:—(1) बोर्ड के अधिवेशन सामान्यतया एक वर्ष में कम से कम छः बार और प्रत्येक विषाही में कम से कम एक बार होंगे।

(2) बोर्ड का अधिवेशन, राष्ट्रीयकृत बैंक के मुख्य कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थानों पर होगा जो बोर्ड विनिर्दिष्ट करे।

(3) बोर्ड के किसी अधिवेशन के लिए सामान्यतया कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायगी और ऐसी सूचना प्रत्येक निदेशक को उस पते पर भेजी जाएगी जो उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाता है।

(4) बोर्ड के किसी अधिवेशन में, उसके अध्यक्ष और उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सहमति के सिवाय उस काम काज से जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया था, भिन्न किसी काम काज का संयोजन तब तक नहीं किया जाएगा तब तक ऐसे काम काज की एक सलाह की सूचना लिखित रूप में अध्यक्ष को न दी गई हो।

(5) बोर्ड के किसी अधिवेशन के लिए गणपूर्ति पांच निदेशकों से होगी :

परन्तु जहाँ उपखंड (8) के उपबन्ध के कारण, कोई निदेशक अधिवेशन में मत देने से अग्रमर्थ है वहाँ ऐसे अधिवेशन के लिए उस कामकाज के संव्यवहार के लिए गणपूर्ति चार में होगी।

(6) यदि, किसी कारण से अध्यक्ष बोर्ड के अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो प्रबन्ध निदेशक उक्त अधिवेशन को अध्यक्षता करेगा और प्रबन्ध निदेशक की अनुपस्थिति में या एक ही व्यक्ति के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक होने की दशा में, अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों द्वारा अपने में से निर्वाचित कोई अन्य निदेशक, अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(7) अधिवेशन में सभी प्रश्नों का विनिश्चय, उपस्थित और मतदान करने वाले निदेशकों के मतों की बहुसंख्या से किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

(8) कोई निदेशक, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी ओर से की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी संधि, उधार, ठहराव या प्रस्थापना से सम्बन्ध या हितवन्ध है, मुसंगत परिस्थितियों की जानकारी होने के पश्चात् यथाशीघ्र बोर्ड के प्रति अपने हित की प्रकृति को प्रकट करेगा और जब किसी ऐसी संधि, उधार, ठहराव या प्रस्थापना पर विचार-विमर्श किया जा रहा हो तब बोर्ड के अधिवेशन में तब तक उपस्थित नहीं होगा जब तक कि उसकी उपस्थिति की बोर्ड के अन्य निदेशकों द्वारा जानकारी प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए अपेक्षा न की जाए और इस प्रकार उपस्थित होने के लिए अपेक्षित कोई निदेशक, किसी संधि, उधार, ठहराव या प्रस्थापना पर मत नहीं देगा।

परन्तु इस उपखंड की कोई बात, ऐसे निदेशक को केवल उस कारण से लागू नहीं होगी कि वह-

- (1) कम्पनी अधिनियम, (1956 का 1) में परिभाषित किसी पब्लिक कम्पनी या भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम में या किसी ऐसी सहकारी सोसाइटी में, जिस के साथ या जिससे राष्ट्रीयकृत बैंक से कोई संधि, उधार, ठहराव या प्रस्थापना की है या किए जाने की प्रस्थापना की है, सम्बन्ध-पूर्वी का दो प्रतिशत से अधिक धारण करने वाला (निदेशक से भिन्न) शेयर धारक है; या
- (2) राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी है यदि वह खंड 3 के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) के अधीन नियुक्त किया गया निदेशक है।
- (9) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों की एक प्रति, अधिवेशन के पश्चात् निदेशकों की जानकारी के लिए, यथाशीघ्र परिचालित की जाएगी और उस या ठीक अनुवर्ती अधिकारी के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होगी।
- (10) बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही ऐसे बोर्ड में कोई रिक्त या उसके गटन में कोई छुटि के होने के आधार पर ही अविधिमान्य नहीं होगी।

### अध्याय 3

#### बोर्ड की समितियाँ

13 प्रबन्ध समिति--(1) राष्ट्रीयकृत बैंक की एक प्रबन्ध समिति होगी।

(2) प्रबन्ध समिति, अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, खंड 3 के उपखंड (8) और (ज) के अधीन नियुक्त निदेशकों और रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट चार अन्य निदेशकों से मिलकर बनेगी।

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक एक बार में एक वर्ष से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा।

(3) प्रबन्ध समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो उसे केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से बोर्ड द्वारा प्रत्ययोजित की जाएँ और केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा अनुमोदन, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् दिया जाएगा।

(4) प्रबन्ध समितियों के अधिवेशन, सामान्यतया मास में दो बार हो सकेंगे।

(5) प्रबन्ध समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार निदेशकों से होगी।

(6) प्रबन्ध समिति के किसी अधिवेशन का कार्यवृत्त अधिवेशन के पश्चात् यथाशीघ्र बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

(7) प्रबन्ध समिति के अधिवेशन और कार्यवाहियाँ बोर्ड के अधिवेशनों और कार्यवाहियों का विनियमन करने के लिए इस स्कीम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों द्वारा, जहाँ तक वे उनकी लागू होने हैं, शासित होंगे।

14 सलाहकार समितियाँ--बोर्ड ऐसी अन्य समितियाँ गठित कर सकेगा, चाहे उसमें पूर्णतः निदेशक हों या पूर्णतः अन्य व्यक्ति हों या भागत निदेशक और भागतः अन्य व्यक्ति हों, जो वह ठीक समझे, जो बोर्ड को ऐसे विषयों के सम्बन्ध में परामर्श देंगी जो उसे साधारणतया या विशिष्टतया निश्चित किए जाएँ और ऐसे कर्तव्यों का जो बोर्ड उन्हें सौंपे पालन करेंगी।

### अध्याय 4

#### प्रकीर्ण

15 खंड 14 के अधीन गठित समिति की सदस्यता के लिए निरहताएँ और किसी सदस्य द्वारा पद का रिक्त किया जाना--(1) कोई व्यक्ति खंड 14 के अधीन गठित किसी समिति का सदस्य नामनिर्दिष्ट किए जाने या सदस्य होने के लिए निरहता होगा यदि वह खंड 10 में विनिर्दिष्ट निरहताओं में से किसी से ग्रस्त है या ग्रस्त हो जाता है।

(2) यदि खंड 14 के अधीन गठित किसी समिति का कोई सदस्य खंड 10 में विनिर्दिष्ट निरहताओं में से किसी से ग्रस्त हो जाता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है और तब ऐसा पद रिक्त हो जाएगा।

(3) खंड 14 के अधीन गठित किसी समिति का कोई सदस्य बोर्ड को सूचना देकर अपने पद का त्याग कर सकेगा और ऐसा त्यागपत्र, बोर्ड से त्यागपत्र की संसूचना की प्राप्ति पर प्रभावी होगा।

(4) बोर्ड खंड 14 के अधीन गठित समिति के किसी सदस्य को हटा सकेगा और उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा।

16 पारिश्रमिक और यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति--(1) निदेशक जो अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक, जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक है, नहीं है या रिजर्व बैंक अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार के किसी पदधारी को उस राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जिसका वह निदेशक है, बोर्ड या बोर्ड की किसी समिति के अधिवेशनों में भाग लेने के लिए या राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई अन्य कार्य करने के लिए इतनी फीस संवत् की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् विनिश्चित की जाए।

(2) उन फीस के अतिरिक्त जिसके संदाय का कोई निदेशक उपखंड (1) के अधीन हकबार हो, प्रत्येक ऐसे निदेशकों को जो राष्ट्रीयकृत बैंक के कार्य के सम्बन्ध में यात्रा करता है, यात्रा और ठहरने के व्यय की, यदि कोई हो, प्रतिपूर्ति ऐसे आधार पर की जाएगी जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् नियत किया जाए।

परन्तु अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक की, जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक है, या रिजर्व बैंक अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी पदधारी को यात्रा और ठहरने के व्यय की प्रतिपूर्ति ऐसे आधार पर की जाएगी जो उस शासित करने वाले नियमों के अधीन उस पर लागू होता है।

(3) खंड 14 के अधीन गठित किसी समिति के किसी सदस्य को दत्तनी कीस तथा यात्रा और ठहरने का व्यय मिलेगा जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाए।

17. बोर्ड के अधिवेशन के बिना संकल्प का विधिमाम्य होना—यथास्थिति, बोर्ड के या प्रबन्ध समिति के सदस्यों की बहुसंख्या द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षरित संकल्प विधिमाम्य और प्रभावी होगा और, यथास्थिति, बोर्ड या प्रबन्ध समिति द्वारा उस तारीख को जिसकी अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता ने उस संकल्प पर हस्ताक्षर किए थे, पारित संकल्प समझा जाएगा।

परन्तु प्रोक्त रूप से पारित संकल्प, यथास्थिति, बोर्ड या प्रबन्ध समिति के अगामी अधिवेशन के समक्ष रखा जाएगा।

परन्तु यह और कि यदि विसम्मति प्रकट करने वाला कोई निदेशक या सदस्य लिखित रूप में यह अपेक्षा करे कि इस प्रकार पारित कोई संकल्प, यथास्थिति, बोर्ड या प्रबन्ध समिति के अधिवेशन के समक्ष रखा जाए तो संकल्प प्रोक्त रूप से विधिमाम्य और प्रभावी नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसे ऐसे अधिवेशन में पारित न कर दिया जाए।

18. खंड 14 के अधीन गठित समितियों के अधिवेशन—खंड 14 के अधीन गठित किसी समिति के अधिवेशनों का विनियमन ऐसी रीति से किया जाएगा जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित की जाए।

### अध्याय 5

#### समावत्त पूंजी

19. समावत्त पूंजी में वृद्धि—इस शर्त के अधीन रहते हुए कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की समावत्त पूंजी, किसी भी वषार में, पन्द्रह करोड़ रुपये से अधिक न हो जाए, किसी ऐसे बैंक की समावत्त पूंजी में, नीचे के उपखंड (क) या उपखंड (ख) या दोनों के अनुसार, समय-समय पर वृद्धि की जा सकेगी :—

(क) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का निदेशक बोर्ड, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन ऐसे बैंक द्वारा स्थापित प्रारंभित निधि में से विनिश्चित रकम अपनी पूंजी में अन्तर्लित कर सकेगा;

(ख) केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श करके किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की समावत्त पूंजी में किसी विनिश्चित रकम का अभिघाय कर सकेगी।

#### अनुसूची

#### [खण्ड 2(ज) देखिए]

विषय :—राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्य कर रहे संघों की सदस्यता के सत्यापन के लिए प्रक्रिया।

मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्ध मण्डलों से उनके अपने-अपने बैंकों में कार्य कर रहे सभी रजिस्ट्रीकृत संघों के नाम

और पते प्रस्तुत करने का अनुरोध करेगा। प्रबन्ध मण्डलों से प्राप्त संघों की विनिश्चित व्यवस्था संघों के रजिस्ट्रार के अभिलेख से यह जांच-पड़ताल करने के लिए सम्बन्धित प्राधिकार श्रम आयुक्तों को अग्रणीत की जाएगी कि क्या उन संघों का रजिस्ट्रीकरण अभी विद्यमान है और क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में अन्य रजिस्ट्रीकृत संघ कार्य कर रहे हैं। प्रादेशिक श्रम आयुक्त अपनी जांच-पड़ताल के परिणामों की रिपोर्ट मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को भेजेंगे। इस जानकारी की प्राप्ति पर, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) संघों से अपनी सदस्यता के दावों को उपबन्ध-1 में पांच प्रतियों में, एक विनिश्चित तारीख तक प्रस्तुत करने का अनुरोध करेगा।

2. तत्पश्चात् सदस्यता के प्रत्यक्ष सत्यापन के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत संघों या आवंटन सत्यापन, अधिकारियों के बीच किया जाएगा। सत्यापन अधिकारी संघों से विभिन्न शाखाओं का कार्यालयों में (बैंकवार) अपने उन सदस्यों की सूची, जिन्होंने गणना की तारीख से जो उस मास से ठीक पूर्ववर्ती मास की पहली तारीख होगी जिसमें केन्द्रीय सरकार ने मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को सत्यापन करने के लिए लिखा हो, पूर्ववर्ती छह मास की अवधि के दौरान कम से कम तीन मास के लिए चन्दा संदत्त किया हो और उपबन्ध 2 में तीन प्रतियों में निम्नलिखित के साथ नियत स्थान और समय पर अपने सभी प्रथम सूचना की प्राप्ति की तारीख से बस दिन के भीतर रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा पेश करने के लिए कहेंगे :—

- (1) सदस्यता एवं चन्दा रजिस्टर;
- (2) रसीदों के प्रतिपत्र;
- (3) रोकड़ और लेखा बहियां;
- (4) बैंक बहियां;
- (5) संघ के संविधान की प्रति;
- (6) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र;
- (7) यदि संघ किसी अखिल भारतीय या राज्य परिसंघ या केन्द्रीय संगठन के साथ सम्बन्ध है तो सम्बन्ध प्रमाण-पत्र और संघाय रसीदें;
- (8) व्यवसाय संघ रजिस्ट्रार को पेश की गई अन्तिम वार्षिक विवरणी की प्रति;
- (9) पदाधिकारियों की सूची; और
- (10) कार्यवृत्त पुस्तिका।

3. यदि संघ अपने सदस्यों की सूची और अन्य अभिलेख पेश करने में असफल रहता है तो उसे दूसरी और अन्तिम सूचना रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जाएगी जिसमें उससे दूसरी और अन्तिम सूचना की प्राप्ति की तारीख से बस दिन के भीतर उनको नियत स्थान और समय पर पेश करने के लिए कहा जाएगा। यदि संघ दूसरी बार भी पेश करने में फिर से असफल रहता है तो उसका सदस्यता का सत्यापन करने के लिए आगे और कोई प्रयत्न नहीं किया जाएगा। किन्तु उन संघों के बारे में जिन्होंने सूचियां और अभिलेख प्रस्तुत कर दिए हैं, सत्यापन अधिकारी उसकी जांच करेगा और उन सदस्यों की संख्या अभिविनिश्चित करेगा जिन्होंने गणना की तारीख से पूर्ववर्ती छह मास की अवधि के भीतर तीन मास का चन्दा संवत्त कर दिया था। यह जांच शत-प्रतिशत होगी और सम्बन्धित संघ के पदाधिकारियों की उपस्थिति

में, किन्तु विरोधी संघ के पदाधिकारियों या प्रतिनिधियों की उपस्थिति में नहीं की जाएगी। सव्यवस्था का स्थापन करने समय, सत्यापन अधिकारी उन अभ्यावेदनों का सम्यक ध्यान रखेगा जो उसे संघ के पदाधिकारियों द्वारा दिए जाएंगे।

4. तत्पश्चात् सत्यापन अधिकारी राष्ट्रीयकृत बैंक के केन्द्रीय या राजस्वीकृत कार्यालय का निरीक्षण करेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार सत्यापित तथा सूची में सम्मिलित सदस्यों के नाम गणना की तारीख को प्रबन्ध मण्डल के रोल पर हैं। वे सभी सदस्य जिनके नाम गणना की तारीख को प्रबन्ध मण्डल के रोल पर नहीं हैं, सूची से निकाल दिए जाएंगे। सत्यापन अधिकारी बैंक के केन्द्रीय या राजस्वीकृत कार्यालय के निरीक्षण के समय गणना की तारीख को बैंक की अपनी-अपनी शाखाओं या कार्यालयों में नियोजित व्यक्तियों की संख्या भी अभिप्राप्त करेगा।

5. तत्पश्चात् सत्यापन अधिकारी सम्बन्धित संघ या संघों के परिसंघों को लिखित रूप में सूचित करेगा कि बैंक में उनके अपने-अपने सदस्यों की सत्यापित सूचियाँ नियत समय और स्थान पर संघ के प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण के लिए तैयार हैं। इसी के साथ ही संघ को भी सूचना दे दी जाएगी कि विरोधी संघ (संघों) के सदस्यों के सत्यापित सूची के निरीक्षण के पश्चात् उन्हें उन सूचियों (विनिर्दिष्टों) के प्रति अपने विनिर्दिष्ट आक्षेपों, यदि कोई हों, निरीक्षण की तारीख से दस दिन के भीतर (या दीर्घतर अवधि के भीतर यदि आक्षेपों की संख्या 10,000 से अधिक होने की सम्भावना है तो 10,000 से ऊपर प्रत्येक 2,000 आक्षेपों के लिए एक अतिरिक्त दिन के आधार पर) भेज देने चाहिए। संघों को यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि साधारण और अस्पष्ट आक्षेप जैसे बड़ा-बड़ाकर दिखाई गई सदस्यता, आदि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। आक्षेपों में उन व्यक्तियों के जिनकी किसी संघ की सदस्यता के प्रति आक्षेप किया गया है, नाम और उनके कारण होने चाहिए।

(सत्यापन अधिकारी की उपस्थिति में दिखाई गई सत्यापित सूची के संघ के प्रतिनिधियों को टिप्पण लेने के लिए अनुरोध किया जाएगा, किन्तु उन्हें कोई भी सूची लेने के लिए अनुरोध नहीं किया जाएगा, और न सूचियों की प्रतिलिपि उन्हें दी जाएगी)।

6. तब सत्यापन अधिकारी संघों से प्राप्त आक्षेप, सदस्यों के वैयक्तिक पूछताछ द्वारा निम्नलिखित क्रमबद्ध प्रतिचयन प्रणाली के आधार पर सत्यापित करेगा :-

- (i) यदि किसी संघ द्वारा दी गई आक्षेप सूची में 500 या उससे कम सदस्यों के नाम हैं तो वैयक्तिक रूप से पूछताछ किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 20 प्रतिशत; किन्तु कम से कम 100 होगी;
- (ii) यदि किसी संघ द्वारा दी गई आक्षेप-सूची में 500 से अधिक किन्तु 1000 से अनधिक नाम हैं तो वैयक्तिक रूप से पूछताछ किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 15 प्रतिशत किन्तु कम से कम 100 होगी;
- (iii) यदि किसी संघ द्वारा दी गई आक्षेप-सूची में 1000 से अधिक किन्तु 2000 से अनधिक नाम हैं तो वैयक्तिक रूप से पूछताछ किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 प्रतिशत, किन्तु कम से कम 150 होगी;
- (iv) यदि किसी संघ द्वारा दी गई आक्षेप-सूची में 2000 से अधिक किन्तु 5000 से अनधिक नाम हैं तो वैयक्तिक रूप से पूछताछ किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 5 प्रतिशत, किन्तु कम से कम 200 होगी;
- (v) यदि किसी संघ द्वारा दी गई आक्षेप-सूची में 5000 से अधिक नाम हैं तो वैयक्तिक रूप से पूछताछ किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 2 प्रतिशत, किन्तु कम से कम 250 होगी।

वैयक्तिक पूछताछ के लिए चयन किए गए व्यक्तियों से अन्य बातों के साथ-साथ यह भी पूछा जाना चाहिए कि क्या वे किसी संघ विशेष के सदस्य हैं और क्या उन्होंने गणना की तारीख से छठ् मास का अवधि के भीतर तीन भाग का चन्दा संदित कर दिया है और यदि ऐसा है तो संरक्ष चन्दा की रकम और वे भाग जिनके लिए वह संदित किया गया था। सत्यापन अधिकारी वैयक्तिक रूप से पूछताछ किए गए सदस्यों को, उनको टिकट संख्या, जहाँ काम करते हैं उस अनुभाग का नाम, वैयक्तिक पूछताछ के परिणाम देते हुए, सूची रखेगा।

7. जहाँ प्रतिचयन जाँच से यह प्रकट होता है कि पूछताछ किए गए कुछ सदस्य किसी संघ की सदस्यता से इन्कार कर रहे हैं तो उनके सदस्यों की सूची अनुपाततः उपान्तरित कर दी जाएगी। उदाहरणार्थ यदि अभिलेखों की जाँच पड़ताल करने पर, यह पाया जाता है कि किसी संघ के विधिसाम्य सदस्य 2,000 हैं और मान लो कि विरोधी संघ इन सदस्यों में से 800 पर आक्षेप करता है तो पश्चात् कथित में से 15 प्रतिशत का प्रतिचयन लेना होगा अर्थात् 120 व्यक्तियों से वैयक्तिक रूप से पूछताछ करना होगा यदि वैयक्तिक पूछताछ करने पर यह पाया जाता है कि 120 व्यक्तियों में 30 व्यक्ति अर्थात् 25 प्रतिशत संघ की सदस्यता से इन्कार कर रहे हैं तो, संघ को सदस्य संख्या में से उन 800 व्यक्तियों का जिनकी सदस्यता पर आक्षेप किया गया था 25 प्रतिशत अर्थात् 200, घटा दिया जाएगा। अन्य गणनों में अन्ततः ऊपर से संघ की सदस्यता इस दशा में 1,800 होगी।

2000--(800 का 25 प्रतिशत)--1,800

यदि ऐसे व्यक्ति जो पूछताछ किए जाने पर उस संघ की सदस्यता से जो उनके अपने सदस्य होने का दावा करना है, इन्कार करते हैं, सत्यापन अधिकारी को यह सूचित करते हैं कि वे विरोधी संघ के सदस्य हैं तो सत्यापन अधिकारी उस संघ के सदस्यों की सूची और अभिलेखों से उनकी सदस्यता की जाँच करेगा और उसकी सूची का तबनुसार समायोजन करेगा, अर्थात् उनके नाम विरोधी संघ की सूची में, यदि वे पहले ही उनमें सम्मिलित न हों, जोड़ दिए जाएंगे और शब्द करने वाले संघ की सूची में से, ऊपर वर्णित रीति से अवयोजित कर दिए जाएंगे।

8. उपरोक्त पैरा 6 में वर्णित रूप में वैयक्तिक सत्यापन करते समय सत्यापन अधिकारी किसी संघ या प्रबन्ध मंडल के प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने के लिए अनुरोध नहीं करेगा।

9. सत्यापन कार्य पूरा हो जाने पर, सत्यापन अधिकारी मुख्य श्रम आयुक्त को रिपोर्ट देगा।

\*क्रमबद्ध प्रतिचयन से समान अन्तरालों पर, जिन्हें प्रतिचयन अन्तराल कहा जाता है, के व्यक्तियों की देते हुए सूची से प्रतिचयन अभियेक है। प्रतिचयन अन्तराल--

#### आक्षेप सूची से व्यक्तियों की कुल संख्या

प्रतिचयन में व्यक्तियों की संख्या होना चाहिए

इस प्रकार उदाहरणार्थ यदि, आक्षेप सूची में 400 कर्मकार हैं और 100 कर्मकारों के प्रतिचयन का चयन किया जाता है तो सत्यापन अधिकारी को सूची में से प्रत्येक (400/100वाँ) या चौथे कर्मकार का चयन करना चाहिए। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि सभी दशाओं में सूची में से चौथे नाम से चयन आरम्भ होना चाहिए। पहला प्रतिचयन सूची में का या तो पहला नाम हो सकता है या दूसरा नाम या तीसरा नाम या चौथा नाम। इस प्रकार उदाहरणार्थ यदि पहला नाम पहले प्रतिचयन के रूप में चयन किया जाता है तो पश्चात्तर्ती प्रतिचयन पाँचवें, नौवें या तेरहवें नाम होंगे। किन्तु यदि दूसरा नाम पहले प्रतिचयन के रूप में लिया जाता है तो पश्चात्तर्ती प्रतिचयन, सूची में से छठे, दसवें या चौदहवें नाम होंगे।

## उपाध्याय 1

(बैंक) में संघ के कार्यों की विशेषितियाँ दर्शित करने वाला प्रोफार्मा

क्रम संख्यांक	संघ का नाम और पता	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और रजिस्ट्रीकरण की तारीख	क्या संघ प्राथमिक है या परिसंघ एकक है	सम्बद्धता		वाढाङुन सदस्यता			संघ के सभापति	टिप्पणियाँ
				केन्द्रीय संगठन	राज्य या अखिल भारतीय परिसंघ	उस बैंक की शाखा या कार्यालय के नाम जिसमें संघ कार्य कर रहा है	प्रत्येक शाखा या सदस्यता	प्रत्येक शाखा या कार्यालय में कर्मकार कर्मकारों से भिन्न		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

योग

टिप्पण: यदि संघ एक से अधिक राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्य कर रहा है तो उसे प्रत्येक बैंक के लिए सदस्यता के दावे पृथक्पृथक् प्रोफार्मा में प्रस्तुत करने चाहिए।

## उपाध्याय 2

पहली सूचना

रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा

दूसरी सूचना

भारत सरकार

श्रम मंत्रालय

..... का कार्यालय

तारीख .....

संख्यांक .....

सेवा में .....

महामन्त्रि,

.....

विषय: राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्य कर रहे सघों की सदस्यता का सत्यापन।

प्रिय महोदय,

मेरे राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1980 की प्रथम अनुसूची में यथावर्तिविष्ट राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्य कर रहे सघों की सदस्यता के सत्यापन के लिए प्रक्रिया (प्रति संलग्न) \* सम्बन्ध में ध्यान आकषिप्त करना है और आपसे अनुरोध करता हूँ कि निम्नलिखित को..... (स्थान)..... तारीख को..... भेज दें।

(i) ..... को, अपने सघ की सदस्यता प्रत्येक सदस्य का नाम, पताधान, उन शाखा के कार्यालय के नाम जहाँ वह कार्य कर रहा है और क्या वह कर्मकार है या कर्मकार से भिन्न कर्मकारी है, को दर्शित करने वाली सूची/पुष्पी में केवल उन सदस्यों के नाम होने चाहिए जिन्होंने..... को समाप्त होने वाली छह मास की अवधि के दौरान कम से कम तीन मास का चन्दा संवत्त कर दिया है और

(ii) (क) सदस्यता-एवं-चन्दा रजिस्टर

(ख) रसीदों के प्रतिपण

(ग) रोकड़ और लेखा बहीय

(घ) बैंक बहीयों

- (क) संघ के सदस्यों की प्रति  
 (ख) रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र  
 (छ) यदि गण किये अखिल भारतीय या राज्य परिषद या केन्द्रीय संगठन के साथ सम्बद्ध है तो सम्बद्धता प्रमाणपत्र और सहाय रसीद ।  
 (ज) व्यवसाय संघ रजिस्ट्रार को पेश की गई अन्तिम वार्षिक विवरणों की प्रति ।  
 (झ) पदाधिकारियों की सूची; और  
 (ञ) कार्यवृत्त पुस्तिका ।

\*\*कृपया इस पर ध्यान दें कि यदि अपेक्षित दस्तावेज ऊपर नियत तारीख को पेश नहीं किए जाते हैं तो आपके संघ की सदस्यता को सत्यापित करने के लिए हमारे कोई प्रयत्न नहीं किया जाएगा ।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति अधिस्वीकृत करें ।

भवदीय,

सहायक आम आयुक्त (केन्द्रीय)

अन प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)

\*\*हूसरी सूचना के लिए

सूचना के लिए प्रतिनिधि निम्नलिखित को प्रेषित :—

- \* (1) सभापति..... (संघ का नाम और पता)  
 \* (2) कोषाध्यक्ष..... (संघ का नाम और पता)  
 (3) प्रादेशिक आम आयुक्त.....  
 (4) मुख्य आम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली ।

सहायक आम आयुक्त (केन्द्रीय)

अन प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय)

[य० फा० 4/5/80-बो०ओ०-1]

अवर सचिव, संयुक्त सचिव

\*नाम से

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

### Banking Division

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 1980

**S.O. 875(E).**—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank, hereby makes the following Scheme, namely :—

### CHAPTER I

#### Introductory

**1. Short title and commencement.**—(1) This Scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

**2. Definitions.**—In this Scheme, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980);  
 (b) "Annexure" means an Annexure appended to this Scheme;  
 (c) "Board" means the Board of Directors constituted under clause 3;  
 (d) "Chairman", in relation to a nationalised bank, means the Chairman of the Board of that bank;

(e) "Director" means a director for the time being of a nationalised bank;

(f) "nationalised bank" means a corresponding new bank constituted under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(g) "representative Union" means a Union registered under the Trade Unions Act 1926 (16 of 1926), or a federation of such Unions, where such Union or federation, as the case may be, is certified, after due verification as having the largest number of workmen employed in the nationalised bank as members who have regularly paid their dues to the Union or to any of the Unions constituting the federation;

Provided that no such Union or federation, as the case may be, shall be deemed, for the purposes of this Scheme, to be a representative Union unless the verified membership of such Union or the Unions constituting the federation, as the case may be, is fifteen per cent or more of the total number of workmen employed by the nationalised bank;

(h) "Schedule" means the Schedule appended to this Scheme;

(i) "verification", with its grammatical variations and cognate expressions, means the verification by the Chief Labour Commissioner (Central) in accordance with the procedure specified in the Schedule;

(j) "Workman" has the meaning assigned to it in clause (s) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947);

(k) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings respectively assigned to them in the Act.



## CHAPTER II

## Board of Directors

3. **Constitution of the Board.**—As soon as may be after the commencement of this Scheme, the Central Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute the Board of a nationalised bank, consisting of—

- (a) not more than two whole-time Directors, of whom one shall be the Managing Director, to be appointed by the Central Government after consultation with the Reserve Bank;
- (b) (i) one Director, from among the employees of the nationalised bank who are workmen, to be appointed by the Central Government from out of a panel of three such employees furnished to it by the representative Union, within a date to be specified by the Central Government, which date shall not be more than six weeks from the date of the communication made by the Central Government requiring the representative Union to furnish the panel of names;

Provided that where the Central Government is of opinion that owing to the delay which is likely to occur in the verification and certification of any Union or federation as a representative Union, it is necessary in the interests of the nationalised bank so to do, it may appoint any employee of the nationalised bank, who is a workman, to be a Director of that Bank.

- (ii) (A) where there is no representative Union to represent the workmen of a nationalised bank, or
- (B) where such representative Union, being in existence, omits or fails to furnish any panel of names within the specified date, or
- (C) where all the persons specified in the panel furnished by the representative Union are disqualified, whether under item (iii) of this sub-clause or under clause 10,

the Central Government may, at its discretion appoint such workman of the nationalised bank, as it may think fit, to be a Director of such bank;

- (iii) a workman of a nationalised bank shall be disqualified for being appointed as a Director unless—

(A) he is, and has been serving for a continuous period of not less than five years in the nationalised bank or in the existing bank of which the nationalised bank is the corresponding new bank, or partly in one and partly in the other, and

(B) he is of such age that there is no likelihood of his attaining the age of superannuation during his term of office as a Director;

- (c) one Director, from among the employees of the nationalised bank, who are not workmen to be appointed by the Central Government after consultation with the Reserve Bank;

- (b) one Director, who, in the opinion of the Central Government is competent to represent the interests of depositors, to be appointed by the Central Government after consultation with the Reserve Bank, from among the depositors of the Bank.

- (e) three Directors, who, in the opinion of the Central Government, are competent to represent respectively the interests of farmers, workers and artisans to be appointed by the Central Government after consultation with the Reserve Bank,

- (f) not more than five Directors, to be appointed by the Central Government after consultation with the Reserve Bank, from among persons having special knowledge or practical experience in respect of one or more matters which are likely to be useful for the working of the nationalised bank;

- (g) one Director who is an official of the Reserve Bank to be appointed by the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank.

Explanation.—For the purposes of this sub-clause, 'an official of the Reserve Bank' includes an officer of the Reserve Bank who is deputed by that Bank under section 54AA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) to any institution referred to therein;

- (h) one Director who is an official of the Central Government to be appointed by that Government.

4. **Custodians to cease to hold office on constitution of the Board.**—On the constitution of the Board every person holding office, immediately preceding such constitution as the Custodian of the nationalised bank, shall cease to hold such office.

5. **Chairman.**—(1) The Central Government shall after consultation with the Reserve Bank, appoint one of the Directors to be the Chairman of the Board.

(2) The Chairman shall preside over the meetings of the Board.

6. **Managing Director.**—The Managing Director shall be the Chief Executive Officer of the nationalised bank and shall exercise such powers and discharge such duties as may be delegated to him by the Board:

Provided that until such delegation is made the Managing Director shall exercise all such powers and perform all such acts, deeds, and things, as the Custodian was authorised to exercise or perform immediately before the date on which the Board was constituted.

7. **Same person may hold office as Chairman and Managing Director.**—The Central Government may, after consultation with the Reserve Bank, appoint the same person to hold, at the same time, both the offices of the Chairman and the Managing Director.

8. **Term of office and remuneration of a whole-time Director including Managing Director.**—(1) A whole time Director, including Managing Director, shall devote his whole time to the affairs of the nationalised bank and shall hold office for such term not exceeding five years as the Central Government may, after consultation with Reserve Bank, specify and shall be eligible for reappointment.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-clause (1), the Central Government shall have the right to terminate the term of office of a whole-time Director, including the Managing Director, at any time before the expiry of the term specified under that sub-clause by giving to him notice of not less than three months in writing or three months' salary and allowances in lieu of notice; and the whole-time Director, including the Managing Director, shall also have the right to relinquish his office at any time before the expiry of the term specified under that sub-clause by giving to the Central Government notice of not less than three months in writing.

(3) A whole-time Director, including the Managing Director, shall receive from the nationalised bank such salary, allowances fees and perquisites, and be governed by such terms and conditions, as the Central Government may determine, after consultation with the Reserve Bank.

(4) If a whole-time Director, including the Managing Director, is, by infirmity or otherwise, rendered incapable of carrying out his duties or is absent on leave or otherwise in circumstances not involving the vacation of his office, the Central Government may, after consultation with the Reserve Bank, appoint another person to act in his place during his absence.

(5) The Central Government may, if it is satisfied that it is expedient in the interests of the nationalised bank so to do, remove a whole-time Director, including the Managing Director, from office:

Provided that no such removal shall be made except after—

- (a) consultation with the Board, and
- (b) giving a reasonable opportunity to the whole-time Director, including the Managing Director, of showing cause against the proposed action.

9. Terms of office of other Director.—(1) A Director appointed under sub-clause (b), (c), (d), (e) or (f) of clause 3 shall hold office for such term not exceeding three years as the Central Government may specify and shall be eligible for reappointment :

Provided that the Central Government may after consultation with the Reserve Bank, remove from office any Director appointed by it under sub-clause (b) (c), (d), (e) or (f) of that clause and appoint in his stead another person to fill the vacancy :

Provided further that no such removal shall be made except after giving a reasonable opportunity to the Director of showing cause against the proposed action.

(2) A Director appointed under sub-clause (g) or sub-clause (h) of clause 3 shall hold office during the pleasure of the Central Government.

(3) A Director, whose term of office has expired, shall notwithstanding such expiry, continue to hold office as a Director until his successor has been appointed.

10. Disqualifications of Directors.—A person shall be disqualified for being appointed as, and for being, a Director.—

(a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors ; or

(b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court ; or

(c) if he has been convicted by a criminal court of an offence which involves moral turpitude.

11. Vacation of office of Director etc.—(1) If a Director becomes subject to any of the disqualifications specified in clause 10, or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.

(2) The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director appointed under sub-clause (g) or sub-clause (h) of clause 3 may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office ; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.

(3) Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-clause, the office of a Director nominated under sub-clause (b) or sub-clause (c) of clause 3 shall become vacant as soon as the Director, ceases to be a workman or an employee, other than a workman, of the nationalised banks of which he is a Director, and the office of a Director nominated under sub-clause (d) of clause 3 shall become vacant on such Director ceasing to be a depositor of the nationalised bank of which he is a Director.

(4) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of a Director, it shall be filled in accordance with clause 3.

(5) A Director nominated under sub-clause (4) in any vacancy in the office of a Director under sub-clause (b), or sub-clause (c) or sub-clause (d) or sub-clause (e) or sub-clause (f) of clause 3 shall hold office for such term not exceeding three years as the Central Government may specify and shall be eligible for reappointment :

Provided that a Director, whether appointed under the proviso to item (i), or under item (ii), of sub-clause (b) of clause 3, shall not hold office for more than six months at a time.

(6) Any other Director appointed to fill a vacancy shall subject to the other provisions of this Scheme, hold office for the period which may be specified by, or during the pleasure of, the Central Government.

12. Meetings of the Board.—(1) Meetings of the Board shall ordinarily be held at least six times in a year and at least once in each quarter.

(2) A meeting of the Board shall be held at the head office of the nationalised bank or such other place as the Board may decide

(3) Ordinarily, not less than fifteen days' notice shall be given of any meeting of the Board and such notice shall be sent to every Director at the address specified by him in this behalf.

(4) No business, other than that for which the meeting was convened, shall be transacted at a meeting of the Board except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the Directors present unless one week's notice of such business has been given in writing to the Chairman.

(5) Five Directors shall be the quorum for a meeting of the Board :

Provided that where, by reason of the provision of sub-clause (8), any Director is unable to vote at a meeting the quorum for such meeting for the transaction of that business shall be four.

(6) If, for any reason, the Chairman is unable to attend a meeting of the Board, the Managing Director shall preside over that meeting and in the absence of the Managing Director or in the event of the Chairman and the Managing Director being the same person, any other Director elected by the Directors present at the meeting from among themselves shall preside at the meeting.

(7) All questions at the meeting shall be decided by a majority of the votes of the Directors present and voting and in the case of equality of votes, the person presiding shall have a second or a casting vote.

(8) A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the nationalised bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal :

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being—

(i) a shareholder (other than a Director) holding not more than two per cent of the paid-up capital in any public company as defined in the Companies Act, 1956, (1 of 1956), or any Corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the nationalised bank has entered into or made, or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal ; or

(ii) an officer or other employee of the nationalised bank, if he is a Director appointed under sub-clause (b) or sub-clause (c) of clause 3.

(9) A copy of the proceedings of such meeting of the Board shall be circulated as soon as possible after the meeting for the information of the Directors and shall be signed by the Chairman of that or the next succeeding meeting.

(10) No act or proceeding of the Board shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy in or any defect in the constitution of the Board.

## CHAPTER III

### Committees of the Board

13. Management Committee.—(1) There shall be a Management Committee of the nationalised bank.

(2) The Management Committee shall consist of the Chairman, the Managing Director, the Directors appointed under sub-clauses (g) and (h) of clause 3 and not more than four other Directors nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank :

Provided that the Director nominated by the Central Government shall hold office for not more than one year at a time.

(3) The Management Committee shall exercise such powers as may be delegated to it by the Board with the approval of the Central Government and such approval shall be given by the Central Government after consultation with the Reserve Bank.

(4) Meetings of the Management Committee may ordinarily be held twice in a month.

(5) Four Directors shall be the quorum for a meeting of the Management Committee.

(6) The minutes of a meeting of the Management Committee shall be laid before the Board as soon as possible after the meeting.

(7) The meetings and proceedings of the Management Committee shall be governed by the provisions contained in this Scheme for regulating the meetings and proceedings of the Board, so far as the same are applicable thereto.

14. Advisory Committees.—The Board may constitute such other committees, whether consisting wholly of Directors or wholly of other persons or partly of Directors and partly of other persons as it deems fit, to render advice to the Board on such matters as may be generally or specially referred to them and shall perform such duties as the Board may entrust to them.

#### CHAPTER IV

##### Miscellaneous

15. Disqualifications for membership of a Committee constituted under clause 14 and vacation of office by a member.—(1) A person shall be disqualified for being nominated as, and for being, a member of a Committee constituted under clause 14 if he is or becomes subject to any of the disqualifications specified in clause 10.

(2) If a member of a Committee constituted under clause 14 becomes subject to any of the disqualifications specified in clause 10, he shall be deemed to have vacated his office and thereupon such office shall become vacant.

(3) A member of a Committee constituted under clause 14 may resign his office by giving notice thereof in writing to the Board and such resignation shall take effect on receipt of communication of the resignation from the Board.

(4) The Board may remove any member of a Committee constituted under clause 14 and appoint another person in his place.

16. Remuneration and reimbursement of travelling expenses.—(1) A Director, not being the Chairman or a whole-time Director, including the Managing Director, or an official of the Reserve Bank or the Central Government shall be paid by the nationalised bank of which he is a Director, such fees, as may be decided by the Central Government after consultation with the Reserve Bank, for attending the meetings of the Board or of any Committee of the Board or for attending to any other work of the nationalised bank.

(2) In addition to the fees to which a Director may be entitled to be paid under sub-clause (1), every such Director travelling in connection with the work of the nationalised bank shall be reimbursed his travelling and halting expenses, if any, on such basis as may be fixed from time to time by the Central Government after consultation with the Reserve Bank :

Provided that the Chairman of a whole-time Director, including the Managing Director, or an official of the Reserve Bank or the Central Government shall be reimbursed his travelling and halting expenses on such basis as may be applicable to him under the rules by which he is governed.

(3) A member of a Committee constituted under clause 14 shall receive such fees and travelling and halting expenses as may be decided by the Board.

17. Resolution without meeting of Board valid.—A resolution in writing signed by the majority of the members of the Board or of the Management Committee, as the case

may be, shall be valid and effectual and shall be deemed to be the resolution passed by the Board or the Management Committee, as the case may be, on the date it was signed, by the last signatory to the resolution :

Provided that any resolution passed as aforesaid shall be placed before the next meeting of the Board or the Management Committee, as the case may be :

Provided further that if any dissenting Director or member requires in writing that any resolution so passed shall be placed before a meeting of the Board or the Management Committee, as the case may be, the resolution shall not be deemed to be valid and effectual as aforesaid unless the same is passed at such meeting.

18. Meeting of committees constituted under clause 14.—The meetings of a Committee constituted under clause 14 shall be regulated in such manner as may be decided by the Board.

#### CHAPTER V

##### Paid-up Capital

10. Increase of paid-up capital.—Subject to the condition that the paid-up capital of a nationalised bank does not, in any case, exceed rupees fifteen crores, the paid-up capital of any such bank may be increased, from time to time, as in sub-clause (a) or sub-clause (b) below or both :—

(a) the Board of Directors of a nationalised bank may, after consultation with the Reserve Bank and with the previous sanction of the Central Government, transfer to its capital a specified amount from the reserve fund established by such bank under sub-section 3 of the Act ;

(b) the Central Government may, in consultation with the Reserve Bank, make contribution of any specified amount to the paid-up capital of a nationalised bank.

#### THE SCHEDULE

[See clause 2(h)]

Subject.—Procedure for verification of membership of unions operating the nationalised banks.

The management of the nationalised banks shall be requested by the Chief Labour Commissioner (Central) to furnish the names and addresses of all the registered unions operating in that respective banks. The particulars of unions received from the managements shall be forwarded to the Regional Labour Commissioners concerned for checking up from the records of the Registrars of Trade Unions whether the registration of these unions is still alive and whether there are other registered unions operating in the nationalised banks. The Regional Labour Commissioners shall report to the Chief Labour Commissioner (Central) the results of their checking. On receipt of this information, the unions shall be requested by the Chief Labour Commissioner (Central) to furnish their membership claims in quintuplicate in Annexure I by a specified date.

2. The Registered Unions shall, thereafter, be allotted amongst Verification Officers for the purposes of physical verification of the membership. The Verification Officer shall ask the unions in Annexure II by registered Post Acknowledgement Due to produce before him at the stipulated place and time, within ten days from the date of receipt of the first notice, a list of their members, in triplicate, in different branches or offices (bank-wise) who have paid subscription for at least three months during the period of six months preceding the date of reckoning which shall be the first of the month just preceding the month in which the Central Government addresses the Chief Labour Commissioner (Central) to undertake the verification along with :—

(i) Membership-cum-subscription register.

(ii) Counter-foils of receipts.

- (iii) Cash and Accounts Books.
- (iv) Bank books.
- (v) Copy of union's Constitution.
- (vi) Registration Certificate.
- (vii) Affiliation certificate and payment receipts if the union is affiliated to any all-India/or State Federation or Central Organisation.
- (viii) Copy of the latest annual return submitted to the Registrar of Trade Unions.
- (ix) List of office-bearers, and
- (x) Minutes Book.

3. If a union fails to produce the list of its members and other records, a second and final notice shall be given by Registered Post Acknowledgement Due asking it to produce them at the stipulated place and time within ten days from the date of receipt of the second and final notice. If the union again fails to produce them on the second occasion also, no further attempt shall be made to verify its membership. However, in respect of the unions which have submitted the lists and records, the Verification Officer shall examine them and ascertain the number of members who had paid three months' subscription within the period of six months preceding the date of reckoning. This examination shall be 100 per cent and shall be done in the presence of the office-bearers of the union concerned but not in the presence of the office-bearers or representatives of a rival union. While doing the verification of membership, the Verification Officer shall give due consideration to any representations which the union officials might make to him.

4. The Verification Officer shall, thereafter, visit the Central or Registered Office of the nationalised bank and ensure that the names of members thus verified are included in the list are borne on the rolls of the management on the date of reckoning. All those members whose names are not borne on the rolls of the management on the date of reckoning shall be eliminated from the list. The Verification Officer shall also obtain the number of persons employed in the respective branches or offices of the bank on the date of reckoning at the time of his visit to the Central or Registered Office of the bank.

5. The Verification Officer shall, thereafter, intimate in writing to the unions or Federations of unions concerned that the verified lists of their respective members in the bank are ready for inspection by the union representative at an appointed time and place. The union shall also at the same time be informed that after inspection of the verified list of members of the rival union(s), they should send, in writing, their specific objections, if any, to the entries in these lists, within 10 days (or the longer period if the number of objections is likely to exceed 10,000 on the basis of one additional day for every 2,000 objections over and above, 10,000) of the date of inspection. It should be made clear to the unions that general and vague objections like inflated membership shall not be considered, the objections should give names of persons whose membership of a union is objected to and the reasons therefor.

(The union representatives shall be allowed to make notes from the verified lists shown to them in the presence of the Verification Officer; they shall, however, not be allowed to take any of the lists, nor a copy of the lists shall be given to them).

6. The objections received from the Unions shall then be verified by personal interrogation by the Verification Officer, of the members on the basis of the following systematic sampling system :—

- (i) If the objection lists furnished by a Union consists of 500 or less names of members, the number of persons to be personally interrogated should be 20 per cent subject to a minimum of 100;
- (ii) If the objection list furnished by a union consists of more than 500 but not more than 1000 names, the

number of persons to be personally interrogated should be 15 per cent subject to a minimum of 100;

- (iii) If the objection list furnished by a union consists of more than 1,000 but not more than 2,000 names, the number of persons to be personally interrogated should be 10 per cent subject to a minimum of 150;
- (iv) If the objection list furnished by a union consists of more than 2,000 but not more than 5,000 names, the number of persons to be personally interrogated should be 5 per cent subject to a minimum of 200; and
- (v) If the objection list furnished by a union consists of more than 5,000 names, the number of persons to be personally interrogated should be 2 per cent to a minimum of 250;

The persons selected for personal interrogation should among other things be asked whether they are members of a particular union and whether they had paid subscriptions for 3 months within a period of six months from the date of reckoning and if so, the amount of subscription paid and the months for which it was paid. The Verification Officer shall maintain a list of members personally interrogated giving their ticket numbers, names of section where working and the result of personal interrogations.

7. Where the sample check reveals that certain members interrogated deny membership of a union, its list of members shall be modified proportionately. For example, if on checking records, it is found that a union has 2,000 valid members and the rival union objects, to say, 800 of these members, a 15 per cent sample of the latter has to be drawn, that is to say, 120 persons have to be interrogated personally. If on personal interrogation it is found that 30 of the 120 persons, (that is to say, 25 per cent) deny membership of the union, the strength of the union shall be reduced by 25 per cent of 800 persons whose membership was objected to, that is to say, by 200. In other words, the final strength of the union shall, in this case be 1,800.

[2000—(25 per cent of 800)—1,800]

If the persons who, on interrogation, deny their membership of the union claiming them as their members, inform the Verification Officer that they are members of a rival union, the Verification Officer shall check their membership with the list of members and records of that union and adjust its list accordingly, that is to say, their names shall be added to the list of the rival union if they are not already included in it, and excluded, in the manner mentioned above, from the list of the claimant union.

8. While conducting personal verification as mentioned in paragraph 6 above, the Verification Officer shall not allow the representative of any union or management to be present.

9. On completion of the verification work, the Verification Officer shall furnish a report to the Chief Labour Commissioner.

A systematic sample means sampling from a list by taking individuals at equally spaced intervals called sampling intervals. The sampling interval should be :

**Total number of persons in the objection list**  
**number of persons in the sample**

Thus, for example, if there are 400 workers in the objection list and a sample of 100 workers is to be selected the Verification Officer should select every (400/100th) or 4th worker in the list. It is, however, not necessary that in all cases the selection should begin from the 4th name in the list: the first sample may either be the 1st Name in the list; or the second, or the third or the fourth. Thus, for example, if the 1st name is selected as the first sample then subsequent samples will be 5th, 9th or 13th names; if, however, the second name is taken as the first sample the subsequent samples would be 6th, 10th or 14th names in the list.

## ANNEXURE I

Proforma showing particulars of Union functioning in  
(Bank)

S. No.	Name and address of the union	Registra- tion No. & date of Registration	Whether the union is a primary or federa- ting unit	Affiliation		Claimed Membership			Name of the Presi- dent, General Secretary Treasurer of the Union with their postal addresses	Remarks
				Central Organisa- tion	State or All India Federation	Name (s) of the Branch or Office of the bank in which union is operating	Membership in each branch or office			
							Workmen	Other than workmen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

TOTAL

NOTE : If the union is functioning in more than one nationalised bank, it should submit membership claims for each bank in a separate proforma.

## ANNEXURE II

First notice  
Second note

By Regd.  
A.D.

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF LABOUR

Office of the

Dated the

No.

To

The General Secretary,

Subject :—Verification of membership of unions operating in the nationalised banks.

Dear Sir,

I am to invite a reference to the procedure for verification of membership of unions (operating in the nationalised banks (copy enclosed) as specified in the Schedule to the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and to request you to furnish—

- (i) a list of membership of your union as on—showing the name of each member, designation, branch or office where working and whether workman or other than workman employee. The list should contain only the names of those members who have paid at least 3 months' subscription during the period of six months ending with—; and
- (ii) (a) Membership-cum-subscription register.
- (b) Counterfoils of receipts
- (c) Cash and account books
- (d) Bank books
- (e) Copy of the Union's constitution
- (f) Registration Certificate
- (g) Affiliation certificate and payment receipt if the union is affiliated to any all-India or State Federation or Central Organisation.
- (h) Copy of the latest annual return submitted to the Registrar of Trade Unions.

- (i) List of office-bearers; and  
(j) Minutes Book

at \_\_\_\_\_ hours on \_\_\_\_\_ (date) at \_\_\_\_\_  
(place)

\*\*It may please be noted that in case the required documents are not produced on the above fixed date, no further attempts will be made to verify the membership of your union.

Kindly acknowledge receipt of this letter.

Yours faithfully,

Assistant Labour Commissioner (C)

Labour Enforcement Officer(C)

\*\*For 2nd notice

Copy forwarded for information to :—

- \* (1) The President, \_\_\_\_\_ (Name and address of the union)  
\* (2) The Treasurer, \_\_\_\_\_ (Name and address of the union)  
\* (3) Regional Labour Commissioner.  
(4) Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi.

By name.

Assistant Labour Commissioner (C)

Labour Enforcement Officer (C)

[No.F.4/5/80-BO.I]

BALDEV SINGH, Jt. Secy.